रबी की फसलों के समर्थन मूल्य

790. **श्री राम गोपाल यादव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोआई के मौसम के शुरू होने से पूर्व रबी की फसलों के समर्थन मूल्यों की घोषणा न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने समर्थन मूल्यों के संबंध में कोई दिशा निर्देश तैयार किए थे;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष सरकार ने भारतीय किसानों से 280 रु. प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदा था जबकि इसे आयातित गेहूं के लिए दुगुना मूल्य देना पड़ा; और

(ङ) यदि हां, तो देश के अन्दर खरीदे गए गेहूं तथा विदेशों से खरीदे गए गेहूं की मात्रा कितनी-कितनी है और उनकी अलग-अलग लागत कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) प्रत्येक वर्ष कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं रबी फसलों की खरीद/न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की सुझाई गई तिथियां, जैसा कि ''कृषि मूल्य नीति—एक दीर्घ अवधि परिप्रेक्ष्य'' नामक शीर्षक के दस्तावेज में निहित है, क्रमशः जून एवं अगस्त है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने 1993-94 मौसम में विपणन किए जाने वाले 1992-93 की रबी फसलों के लिए मूल्य नीति पर 24-7-1992 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। बाद में, उर्वरकों के मूल्यों में हाल के संशोधन को देखते हुए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने 8-9-1992 को एक पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकार इस समय 1992-93 की रबी फसलों की मूल्य नीति पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(घ) और (ङ) 1992-93 के रबी विपणन मौसम हेतु निर्धारित किए गए 250 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त, केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं की खरीद बढ़ाने के लिए, 1 अप्रैल 1992 से 30 जून, 1992 की अवधि के दौरान किसानों द्वारा भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य खरीद एजेंसियों को बेचे गए गेहूं पर 25 रुपए प्रति क्विंटल का केन्द्रीय बोनस भी प्रदान किया गया। पंजाब, हरियाणा, एवं राजस्थान ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं केन्द्रीय बोनस से अधिक 5 रुपए प्रति क्विंटल का राज्य बोनस प्रदान किया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित राज्य बोनस 25 रुपए प्रति क्विंटल था। दिनांक 20-11-1992 को 1992-93 विपणन मौसम के दौरान गेहूं की 63.80 लाख मीटरी टन की मात्रा की खरीद की गई है।

गेहूं के आयात हेतु 2,990 मिलियन मीटरी टन गेहूं के लिए करार किया गया है। अनुमानित भारित औसत सी. आई. एफ. लागत 3823 रुपए प्रति मीटरी टन से 4657 रुपए प्रति मीटरी टन के बीच है।

कीटनाशी/विनाशक जीवनाशी की कीमतें

791. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसान तथा बागवान कीटनाशी/विनाशक जीवनाशी की कीमतों में निरन्तर वृद्धि से चिन्तित हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उन्हें राहत प्रदान करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) सरकार ने उचित मूल्यों पर कृमिनाशकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) कृमिनाशकों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त 44 कच्चे माल पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं है।

(2) कृमिनाशक उद्योग में प्रयुक्त अधिकतर अंतवर्ती और मूल सामग्री पर 65 प्रतिशत की दर पर रियायती सीमा शुल्क लगाया जाता है।

(3) 19 तकनीकी ग्रेड सामग्री पर 75 प्रतिशत की रियायती दर पर सीमा शुल्क लगाया जाता है ।

Review of Oilseed trade Policy

792. DR. SANJAY SINH : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Technology Mission for Oilseeds has recently called for a review of the oilseed Trade Policy in India taking into account the new economic policies of Government;

(b) if so, what are the details in this regard; and

(c) what decision Government have taken in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN) :

(a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

मध्य प्रदेश में बाढ़

793. **श्री कैलाश नारायण सारंग** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने सितम्बर, 1992 में राज्य के पूर्वोत्तर जिलों में आई बाढ़ तथा भारी वर्षा के कारण हुई जन-धन की हानि के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी है जिसमें उक्त प्रयोजन के लिए अतिरिक्त सहायता देने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार से कितनी अतिरिक्त सहायता राशि की मांग की गई है और अब तक प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण है और यह सहायता राशि राज्य सरकार को कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) राहत उपायों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र से 9.00 करोड़ रुपए की सहायता मांगी थी । राज्य सरकार के निवेदन पर वित्तीय राहत व्यय की वर्तमान योजना को मद्देनजर रखते हुए विचार किया गया था । आपदा राहत निधि के केन्द्रीय अंश की चौथी त्रैमासिक किस्त की 693.75 रुपए की राशि अग्रिम रूप से मध्य प्रदेश सरकार को निर्मुक्त की जा चुकी है ताकि प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को चलाया जा सके ।

Prawn Culture Project in Orissa

794. SHRI GURUDAS DAS GUPTA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that leading environmentalists, jurists, social activists and political leaders have strongly denounced the Prawn Culture Project at Chilka lake in Orissa and appealed to the Centre and the Tatas to call off the project; and

(b) if so, the details thereof and Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN) : (a) and (b) Yes, Sir. A number of representations have been received regarding environmental implications of Joint-sector Prawn Culture Project of Government of Orissa and Chilka Aquatic Farms Ltd., in Chilka Lake. The Government of Orissa have been advised to undertake a detailed environmental impact study of the project by a multi-disciplinary group.

Expansion of Lift Irrigation facilities in Orissa

795. SHRI BISHAMBHAR NATH PANDE : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Orissa Government would receive German Credit around Rs. 70 crores for expansion of the Lift Irrigation facilities;

(b) whether it is also a fact that Credit assistance would be utilized for installation of 1000 lift irrigation points; and

(c) if so, what are the details thereof ?